

LOK SABHA

Monday, June 26, 1967/Asadha 5, 1889  
(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of  
the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Centre-States Relations

+

- \*721. Shri Prakash Vir Shastri:  
Shri Bibhuti Mishra:  
Shri K. N. Tiwary:  
Shri Hukam Chand Kachwal:  
Shri Raghuvir Singh Shastri:  
Shri Shiv Kumar Shastri:  
Shri Mahant Digvijai Nath:  
Shri Y. S. Kushwah:  
Dr. Surya Prakash Puri:  
Shri Ram Avtar Sharma:

Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) whether differences between the Central Government and some State Governments are increasing;

(b) if so, the main issues on which they differ; and

(c) the steps so far taken to resolve these differences and the result thereof

The Deputy Minister (Dr. Sarejini Maheshi): (a) to (c). In a country of the size of India, functioning within the framework of a federal Constitution such as ours, occasional differences between the Centre and States are unavoidable. They have existed in the past. With the coming into power, after the last Elections, of State Governments representing different political complexions, these differences naturally tend to acquire a new dimension.

They relate to obvious questions like financial, food, Plan and other allocations to the States. Occasionally other issues such as the handling of gherao activities in West Bengal or the use of AIR facilities also arise.

As in the past, attempts are made to resolve all such questions either by correspondence, personal discussion or conferences of Chief Ministers.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : केन्द्र और राज्यों के बीच पारस्परिक मतभेद बढ़ते चले जा रहे हैं और जैसा अभी उप मंत्री जी के वक्तव्य से प्रकट हुआ कि चुनावों के पश्चात् उनमें और वृद्धि हुई है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई है, मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार के मतभेद विशेष रूप से किन किन राज्यों से अधिक हैं और जहाँ ये मतभेद हैं वहाँ क्या आदानों और दूसरी समस्याओं के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी प्रश्नों पर मतभेद है जिससे भारत सुरक्षा सम्बन्धी समस्या भी भा जाती है ?

प्रधान मंत्री तथा अन्य उचित मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : यह पूरी तरह से सच तो नहीं है लेकिन कुछ हद तक यह जरूर सच है जैसे हमने खुद कहा कि बेराब इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ मतभेद उठे हैं। लेकिन जैसा कि उत्तर में बतलाया गया है ऐसे मतभेद तो बीड़े बहुत हमेशा ही रहे हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अब बढ़े हैं ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : बढ़े तो बैसे नहीं कह सकते हैं लेकिन कुछ बातें जरूर गई उठी हैं। इस समय कोई विशेष ऐसे

मतभेद तो नहीं हैं जिन के बारे में बातचीत न हो सकती हो और कुछ समझौता न हो सकता हो ।

**श्री प्रकाशचौर शास्त्री :** यह जो मतभेद बुनाबों के बाद कुछ राज्यों के साथ केन्द्र के अधिक बढ़ गए हैं क्या इस में कुछ संवैधानिक कठिनाइयां भी इस प्रकार की उलझ गई हैं जिस के ऊपर केन्द्रीय सरकार और से विचार कर रही हैं ताकि किसी प्रकार के कुछ संशोधन या परिवर्तन किये जा सकें ? दूसरे नक्सलवाड़ी के लिए जो संसद सदस्यों का एक शिष्टमंडल जाने वाला था उसके ऊपर पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को क्या कोई पत्र लिखा था और क्या यह सब नहीं है कि गृह मंत्री के मदन में आश्वासन देने के बावजूद भी वह यात्रा अब स्थगित कर दी गई है ?

**श्रीमती इंदिरा गांधी :** कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे संविधान रास्ते में धाता हो । जहां तक नक्सलवाड़ी का सम्बन्ध है बंगाल की सरकार ने लिखा है कि वहां की स्थिति कुछ सुधर रही है और इसलिए उन्होंने यह आग्रह किया है कि उनकी भौका दिया जाए कि यह काम वे खुद देख सकें . . .

**श्री प्रकाशचौर शास्त्री :** मेरा प्रश्न यह था कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने क्या प्रधानमंत्री को इस सम्बन्ध में कोई पत्र भेजा है कि संसद सदस्यों का शिष्ट मंडल वहां न जाए यदि हां तो प्रधान मंत्री की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ? क्या राज्य सरकारें पालियामेंट के अधिकारों को या संसद के अधिकारों को इस प्रकार से कम भी कर सकती हैं ?

**श्रीमती इंदिरा गांधी :** मुख्य मंत्री का पत्र मुझे मिला है । सवाल यह है कि नक्सलवाड़ी की भाजूक स्थिति है । जिस धक्का यह निष्कर्ष पहुंचा था कि वहां कुछ संसद सदस्य

जायें उस समय उनके अपने मिनिस्टर वहां पर थे और मुख्य मंत्री ने हमको लिखा कि ये अपना काम पूरा कर लें तो शायद अपने नतीजे निकलें ।

**श्री प्रकाशचौर शास्त्री :** अब जाने की अनुमति है ? अब भेज रहे हैं ?

**श्री क० ना० लिबारी :** स्टेटमेंट में कहा गया है कि घेराव और फूड जैसे मामलों को ले कर डिफेंस है । चीफ मिनिस्टर और वहां के होम मिनिस्टर जब आए थे तो उनकी प्रधान मंत्री जी से बातें हुई थीं । घेराव एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर सारे देश का दिमाग लगा हुआ है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इनके सम्बन्ध में भी बात हुई थी क्या इस बारे में आप सब एक मत थे । सेंटर की जो राय है उसको क्या उन्होंने माना है या वे भिन्न विचार रखते हैं ?

**श्रीमती इंदिरा गांधी :** इन दोनों विषयों पर बातचीत हुई है । पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री का कहना है कि घेराव की स्थिति पहले से सुधरी है । हमारे पास जो खबर आई थी और हमने जो विशेष उदाहरण दिये और सुझाव रखे, उनके बारे में मुख्य मंत्री ने कहा कि वे उनपर ध्यान देंगे ।

जहां तक घनाज का प्रश्न है खाद्य मंत्री जी कई दफे बता चुके हैं कि बंगाल की मांग क्या है और यह भी कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना घनाज भेजा जा सके, हम उनको भेजें ।

**श्री रघुबंर सिंह शास्त्री :** बंगाल में घेराव से उत्पन्न स्थिति की संसद में बारबार चर्चा हुई है । मालूम ऐसा पड़ता है कि केन्द्रीय सरकार उस मामले में कुछ अपने आप को विवश अनुभव करती है । वहां के उद्योगों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है । मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्थिति में केन्द्रीय सरकार की स्पष्ट नीति क्या है ? क्या वह बंगाल की सरकार

के साथ सहमती के कोई प्रभावशाली कार्य इस विषय में कर सकेंगी ?

**श्रीमती इंदिरा गांधी :** जाहिर है कि हम उन से हर वक्त चर्चा कर रहे हैं और हमारी कोशिश यह है कि घेराब बन्द हों और जहाँ भी जनता के संग या किसी के भी संग अन्याय हो रहा है वह दूर हो, दोनों की तरफ से। अगर तो वहाँ के मजदूरों के खिलाफ कुछ हुआ है और उनको अगर जायज मांगें हैं तो उनको भी देखना है और जो घेराब नाजायज तरीके से हुए हैं उनको भी रोकना है।

**श्री रामावतार शर्मा :** प्रधान मंत्री महोदय ने बताया कि मतभेद हैं।

मैं जानना चाहता हूँ कि ये मतभेद क्या केवल वहीं हैं जहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकारें हैं या वहाँ पर भी हैं जहाँ कांग्रेसी सरकारें हैं ? क्या जहाँ कांग्रेसी सरकारें हैं उन से भी मतभेद चल रहे हैं ?

**श्रीमती इंदिरा गांधी :** पहले बताया जा चुका है कि ये मतभेद हमेशा से रहे हैं और जो हमारा फंडल स्ट्रक्चर है, उसमें हमेशा रहेंगे भी।

**Shri Krishna Kumar Chatterji:** Will the hon. Prime Minister agree with me that the Central Government, in its eagerness to take a more helpful attitude towards the non-Congress Governments, is depriving some of the State Governments run by the Congress in the matter of food and monetary help?

**Shrimati Indira Gandhi:** No, Sir.

**Shri Hem Barua:** May I know whether it is a fact that recently the Governor of West Bengal summoned a meeting of the District Police Superintendent and the District Magistrate at Raj Bhavan in Calcutta by-passing the State Government, to which the Deputy Chief Minister of West Bengal has taken strong objection, and may I know whether the

Government has instructed the Governor of West Bengal to bypass the State Government and, if so, what is the peculiar bandobast for West Bengal?

**Shrimati Indira Gandhi:** No such instructions have been sent.

**श्री ब्रह्म बिहारी बाजपेयी :** राज्यों की जिम्मेदारियाँ ज्यादा हैं और उनकी प्रामदनी के साधन कम हैं। कम कुछ राज्यों ने सुझाव दिया है कि आल इंडिया टैक्स काउंसिल बनाई जाए जो केन्द्र और राज्यों के बीच में प्रामदनी के शीतों का ठीक तरह से बंटवारा करे ? क्या यह भी सुझाव दिया गया है कि फाइनेंस कमिशन जो पांच साल के बाद नियुक्त होता है वह स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाए जिससे राज्यों को केन्द्र की प्रामदनी में से अधिक हिस्सा मिल सके ? क्या मैं जान सकता हूँ कि केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में विचार किया है, यदि हाँ तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):** May I say that all these questions are being raised but there has been no particular consideration on them because Government does not feel that these things can be done conveniently or that the Constitution can be changed like that. But what is required is to adjust, and if it can be adjusted, we are trying to do.

**Shri Sradhakar Supakar:** There are some State Governments which do not believe in the system of planning as envisaged by our Planning Commission. May I know whether in the case of those States the Centre has tried to have some understanding and modify their own planning or tried to convince those State Governments to see that they accept our system of planning?

**Shrimati Indira Gandhi:** All the States have accepted Planning.

**श्री नयू लिवथे :** क्या उपप्रधान मंत्री जी का ध्यान आन्ध्र के मुख्य मंत्री के कथन

की धोर गया है तथा उसी तरह के केरल के मुख्य मंत्री के बयान की धोर गया है, जिस मूलतः वितीय सहायता का जो इन्तजाय है उसकी जगह पर एक नये कानून बनाये जाने का सुझाव दिया है तथा दूसरे ने संविधान में परिवर्तन किये जाने का सुझाव दिया है ? क्या सरकार के पास ये सुझाव पहुंचे हैं, यदि पहुंचे हैं तो क्या सरकार ने उन पर विचार किया है तथा क्या निर्णय लिया है ?

**Shri Morarji Desai:** This is not the first time that this question has been raised; this question is being raised for the last few years and the question is that the Constitution may be changed regarding the allocation of revenues between the States and the Centre. This has been considered, and it has been found that no particular advantage will be accruing to any State or the Centre if there is any change. This was done after much deliberation, but in order to see that difficulties may not arise or the States may get more allocation than what they are entitled to according to revenues, the system of Finance Commission has been provided in the Constitution which has been working and every five years they take into account the condition of the States' revenues and the Central revenues and allocate certain amounts from various taxes to different States. In addition to normal allocations all the resources are taken into account when the Plan is made, and equitable allotments are made to different States, having regard to the needs of different States. This, I think, is a far more satisfactory arrangement than making blanket allocations of resources to different States. That is not going to increase the revenues of either the State or the Centre.

**श्री डा० ना० तिवारी :** क्या सरकार ने गैर कांग्रेसी सरकारों में ऐसी मनोवृत्ति का साक्षात् पाया है कि वे अपनी असफलताओं को छिपाने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बदनाम कर ज्यादा कन्सेशन देना चाहते हैं ?

**Shri Morarji Desai:** I do not think that it will be right to give this kind of motivation to States. They can give the same motivation to the Centre.

**Shri Jyotirmoy Basu:** The impression in West Bengal is that the Home Minister at the Centre by his actions and speeches has tried to belittle the West Bengal Government thereby giving the feeling that the Centre-State relations have been affected slightly. Will the hon. Prime Minister tell us whether she is going to issue some sort of a directive to her Cabinet colleagues not to behave in that manner in future?

**Shrimati Indira Gandhi:** No Cabinet Minister has behaved wrongly or improperly.

Some hon. Members rose—

**Mr. Deputy-Speaker:** We have already taken 15 minutes on this question. The Centre-State relations cover a very wide area. I will try to accommodate a few more supplementaries; more than that, I cannot allow.

**Mr. Sheo Narain.**

**श्री सिद्ध नारायण :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि नक्सल बाढ़ी में 10 हरिजन स्त्रियों के सिर काटकर फेंक दिये गये, न बंगाल की होम मिनिस्ट्री और न सेन्ट्रल की होम मिनिस्ट्री इसमें कुछ कर पाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर क्या करना चाहती है, वहाँ हुकूमत उनके हाथ में नहीं है, घाउट धाक कन्दोल है, इस माबलम को हल करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

**श्रीमती इंदिरा गांधी :** इस बारे में आंच हो रही है।

**Shri V. Krishnamurti:** This question is very important. We can devote 20 more minutes for this.

**Mr. Deputy-Speaker:** I have already given more than 15 minutes for this question. As I have already said,

Centre-State relations cover a very wide field, and questions from different angles have already been put. I shall permit a few more supplementary questions. Beyond that I cannot permit.

**Shri V. Krishnamurti:** We can devote another 15 minutes to this question.

**श्री कंबर लाल गुप्त :** क्या प्रधान मंत्री महोदया को मालूम है कि कुछ प्रान्तों में सा-एण्ड प्रार्डर की सिचुएशन खराब हो रही है बेराब के कारण से, कुछ जगहों पर रेलवे से भनाज लूटा जा रहा है, कुछ जगहों पर लेबर ट्रबल है इसका कारण यह बताया जाता है कि वहां की जो सरकारें हैं, वे इस मामले में पूरी तरह से कोभापरेट नहीं कर रही हैं। राज्य सरकारों का वर्चन इस बारे में दूसरा है—इस लिये सही चीज क्या है, यह मालूम करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

दूसरे, जी डेलीगेशन पार्लियामेंट का जाने वाला था, वह विलकुल खत्म कर दिया गया है या जाने पर अभी विचार हो रहा है ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ब्यवस्था का प्रश्न है। पार्लियामेन्ट डेलीगेशन जाये, न जाये, इसका प्रश्न प्रधान मंत्री कैसे दे सकती हैं। यह पार्लियामेंट का धपना सवाल है, इसको स्वीकर के साथ तय करना होगा। प्रधान मंत्री के कहने मात्र से डेलीगेशन के जाने या न जाने का सम्बन्ध नहीं है।

**Mr. Deputy-Speaker:** It was not a resolution of the House. It was a suggestion accepted by the Home Minister. Unless there is a resolution accepted by the House, the Speaker does not come into the field. This is my view, so far as this point is concerned.

**Shrimati Indira Gandhi:** I should like to say that it is not Government who have taken a decision on this. When I received the letter from the

Chief Minister of West Bengal, I sent it on to the Speaker.

**Shri Kanwar Lal Gupta:** What is the reply to my question?

मैंने यह कहा है कि वहां पर जो सा-एण्ड-प्रार्डर सिचुएशन खराब हो रही है, उसके बारे में प्रलग प्रलग वर्कन्ड हैं, उस को समझने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है तथा क्या वह डेलीगेशन जायेगा या वह खत्म कर दिया गया है।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** डेलीगेशन के बारे में अभी कहा गया है, कि इसका भेजना हमारे हाथ में नहीं है।

**Shri Tridib Kumar Chaudhuri:** On a point of order. We have just heard Shri A. B. Vajpayee raise a point of order against a question by a Member of his own party. You have decided on the point of order already. So, why is the same question being put again?

**Mr. Deputy-Speaker:** He is asking for information regarding other matters.

**Shri Tridib Kumar Chaudhuri:** He has also mentioned about the parliamentary delegation.

**Shri Virendrakumar Shah:** The hon. Prime Minister could reply at least to the first part of Shri Kanwar Lal Gupta's question.

**Mr. Deputy-Speaker:** Yes, one part of his question still remains to be answered.

**Shrimati Indira Gandhi:** Government are constantly in touch with the situation. We are also in touch with the State Government. As far as the railways are concerned, the State Government asked for special help and that help has been sent.

**Shri V. Krishnamurti:** Is it not a fact that after the general elections in order to embarrass the non-Congress Governments in the various States, the Central Government has cut the financial allocations for the various projects in the States?

Especially, in Madras State, the Tuticorin project has been cut out. Is it not a fact that the Centre has taken such a decision in order to embarrass the Madras Government?

**Shri Morarji Desai:** This is a wrong allegation, based perhaps on want of knowledge. Schemes have been down in all States, and perhaps more in the Congress States than in non-Congress States.

**श्री जयशंकरजी :** उपाध्यक्ष जी, आज बहुत से प्रदेशों में स्थिति बड़ी असामान्य है, खास कर पश्चिमी बंगाल में बहुत असामान्य है। कुछ दिन हुए हमने नक्सलवाड़ी में देखा कि क्या हुआ, फिर हम ने बर्दवान में देखा कि वहाँ पह मजदूरों के बीच में स्थिति खराब हुई, अगले कल परतों हम ने देखा कि पश्चिमबंगाल के एक सेक्टर दड़ो बुरो तरह से चाल चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जबकि हमारे संविधान में यह व्यवस्था है और संविधान के आर्टिकल 256 के मातहत यूनियन बर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप कर सकती है तो मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि इन असामान्य स्थिति में जबकि नक्सलवाड़ी में कोई सरकार नहीं है और जबकि पश्चिमी बंगाल में किसी की जान व माल की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है तो कौन बाधा है कि वहाँ यूनियन सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती . . . (व्यवधान)

**Shri Jyotirmoy Basu:** Are you allowing this question? (*Interruptions*).

**Shri Shashi Ranjan:** Please keep quiet. I am in possession of the House. (*Interruptions*).

**Shri Jyotirmoy Basu:** Actually the M. P. conducted a *hamla* on the young boys there . . . (*Interruptions*).

**Shri S. M. Banerjee:** On a point of order?

**Shri Shashi Ranjan:** Under what rule?

**Shri S. M. Banerjee:** Rule 378. I have been listening to the various questions put by the Congress benches. A ruling has been given in this House, and we have developed a convention also, that this House should not be utilised for damning a State Government. My hon. friend, Shri Shashi Ranjan, for whom I have great regard, has tried to invoke a particular article of the Constitution and now demands Central intervention which is a matter of policy. I want to know whether we shall be permitted in future to utilise this House or this forum for damning a newly-elected non-Congress popular government of the people. (*Interruptions*).

**Mr. Deputy-Speaker:** He referred only to the Naxalbari situation.

**Shri S. M. Banerjee:** No, no, to the whole of Bengal.

**Mr. Deputy-Speaker:** He referred to Bengal in connection with that situation.

**Shri S. M. Banerjee:** Let Members go to Calcutta and other places and see things for themselves. They can move freely. As Shri Jyoti Basu, the West Bengal Minister, has said, this agitation against the State Government is political in character. They do not want to allow the government to function there. This is very clear. Their next target is UP.

**Shri Tridib Kumar Chaudhuri:** On a point of order.

**Shri Surendranath Dwivedy:** Has the point of order of Shri Banerjee been disposed of?

**Mr. Deputy-Speaker:** I have already said that he had no intention to cast any aspersion on the West Bengal Government. He was more particularly interested in knowing about the Naxalbari situation with which we are all concerned. That is all. Hence I have disallowed the point of order.

**Shri Tridib Kumar Chaudhuri:** If you look at the question, it is one of the accepted principles regarding par-

ting questions that the supplementaries should be relevant to the subject-matter of the question.

**Shri Shashi Ranjan:** Centre-State relationship.

**Shri Tridib Kumar Chaudhuri:** I am addressing the Chair, not Shri Shashi Ranjan:

**Shri Jyotirmoy Basu:** Nor Shri Sheo Narain.

**Shri Shashi Ranjan:** I am helping the Chair.

**Shri Tridib Kumar Chaudhuri:** Here the subject is Centre-State relations and in respect of that, the main question purports to ask whether there have any differences, and the Government have denied that there have been any differences. So how does this question about the Naxalbari situation which relates to law and order or the Asansol situation and become in order?

**Mr. Deputy-Speaker:** I perfectly agree that the main question relates to certain differences, if they have arisen, and Government have clarified the position. But because a certain situation had arisen there and we had discussed it, he incidentally referred to it. I would request the hon. Member not to refer to any other matter, particularly to Bengal Government with a view to criticise it.

**Some hon. Members:** Why?

**Mr. Deputy-Speaker:** Because the scope of the question is limited.

**Shrimati Lakshminathanamma:** We read in the papers that Peking has been taking a lot of interest in the Naxalbari situation. Why do you say it should not be referred to? (Interruptions).

**Mr. Deputy-Speaker:** Unless you permit me, I cannot proceed. I am accommodating as many shades of opinion in as many States as possible because the question covers a wide ground, but if you create a situation.. (Interruptions).

**श्री ज्योतिरमोय बासु:** यह पालियामेंट है या कुछ राज्य सरकारों को लेकर सगड़ा करने का सझा बन गया है? कुछ लोग राज्य सरकारों के विरोधी और कुछ राज्य सरकारों के समर्थक हैं और उनका यह सझा बन रहा है, यह हिन्दुस्तान की पालियामेंट है या क्या है यह मैं जानना चाहता हूँ? मैं यह दोनों दृष्टिकोण पसन्द नहीं करता। यह हिन्दुस्तान की पालियामेंट है। क्या मतलब है इसका?

**Shri Surendranath Dwivedy:** You have to regulate the business of the House. You are within your rights to disallow any supplementary which is irrelevant, but can you put a ban saying that no questioner should raise a question about the West Bengal Government? Can there be a ban? You said; you can put a supplementary, but you cannot refer to the West Bengal Government. That is what you said.

**Mr. Deputy-Speaker:** Objection was raised that in this House opportunity is being taken just in a slanting manner to cast some aspersion on certain actions of a State Government. I think this should not be permitted in the present circumstances.

**Shri D. N. Tiwary:** I want one clarification from you.

**Mr. Deputy-Speaker:** Mr. Tiwary, please resume your seat. He has raised a very good question, I want it to be replied to.

**Shri D. N. Tiwary:** In the Third Lok Sabha hundreds of questions were put of this nature, and the State Governments were damned, the Chief Ministers were damned, and now a simple question like this is being objected to. What is this? Two standards.

**Mr. Deputy-Speaker:** As Mr. Limaye has observed, we must also take one thing into consideration. It covers a very wide field, and in the new context of the situation, the State-Centre relation has become a matter on some issues where controversies might

arise. In such a situation, we ought to be very cautious while putting questions.

**Shri D. N. Tiwary:** When it comes to Congress, they are not cautious; when it comes to non-Congress, they are cautious.

**Mr. Deputy-Speaker:** The scope of the question is very limited. Let him finish.

**Shri Shashi Ranjan:** I was asking this question. Article 256 exclusively deals with the relationship between the States and the Union, and I wanted to know from the Prime Minister what fetters her hand from applying article 256 in such a situation in West Bengal when consecutively incidents are happening and people's life and property are almost at stake.... (Interruptions).

**Mr. Deputy-Speaker:** You are referring to a section which is a preliminary for emergency powers. I know that section. So, at this juncture, when we are considering inter-State relationship, please do not refer to it.

**Shrimati Indira Gandhi:** I would merely say that nothing fetters our hands. If the need is felt, if such a situation arises, then the matter can be considered.

**श्री जगन्नाथ राव चौधरी :** तनाव और झगड़ें पैदा होना यह कोई नयी बात नहीं है। केन्द्र और राज्यों के बीच में कांग्रेसी मंत्रिमंडल होते हुए भी तनाव और झगड़ें पैदा हुए हैं। आज जब कि गैर-कांग्रेसी सरकारें कई प्रान्तों में हैं तो भी झगड़ें पैदा होंगे। इसलिये मैं मानना चाहूंगा कि केन्द्र और प्रान्तों में कोई भी झगड़ा या तनाव की स्थिति पैदा होगी तो उसको हल करने के लिये एक स्थायी प्रायोगिक निकाय बनाने का विचार सरकार कर रही है क्या ?

**श्रीमती इंदिरा गांधी :** अभी तो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, भाव्य मामलीय व्यवस्था यहाँ में नहीं

कि ऐसा कुछ भी मतलब उठता है वो प्रायः की बात करके उसका हल हो जाता है।

Several hon. Members rose—

**Mr. Deputy-Speaker:** We have exhausted half an hour. I have permitted all Members to put questions.

**Shri Vasudevan Nair:** All kinds of questions are allowed to be asked from that side. On this side, we are not allowed.

**Mr. Deputy-Speaker:** You see the record and then make a statement. It is not fair. Next question.

Several hon. Members rose—

**Mr. Deputy-Speaker:** I have passed on to the next question.

**श्री मोहन लाल :** अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को आदेश दीजिये कि हम सबन से जायें। प्राय ने हमारी पार्टी को किसी को मौका नहीं दिया। एक पार्टी के छः छः को मौका दिया। तो प्राय कह दीजिये कि हम लोग चले जायें। . . . (स्वभावान) . . .

#### बलचिंत जखोग का राष्ट्रीयकरण

+

\*722. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

श्री श्री० प्र० स्वामी :

क्या सुचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बलचिंत जखोग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy): (a) and (b). The question of nationalisation of the film industry has been considered in all its aspects on several occasions in the past and Government